Ministry of Education Notification G.S.R. No. 1334 (in English) and G.S.I. No. 1335 (in Hindi), dated the 12th July, 1968, publishing the Salar Jung Museum (Amendment), 1968. [Placed in Library. *See* No. LT-1660/68.]

(*Interruptions by Shri Rajnarain*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: No more; please sit down.

श्री राजनारायण : माननीया, मै आप से यह निवेदन करना चाहता हू कि इस सम्बंध मे हमारी बात भी सुन ली जाय ।

SHRI BHUPESH GUPTA: You hear him for a minute.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now Mr. Dahyabhai Patel.

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON SALARY, ALLOWANCES AND OTHER AMENITIES TO MEMBERS OF PARLIAMENT

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Madam, I lay on the Table a copy of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Salary, Allowances and other Amenities to Members of Parliament.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Madam Deputy Chairman, I have a submission to make here. Even before he laid it on the Table of the House we came to know of the preposterous recommendation increasing the allowances of Members of Parliament to Rs. 51; we knew it before. Madam, how did it leak out? We should like to know who leaked out such a preposterous recommendation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhupesh Gupta, you cannot raise questions like this and take the time of the House.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Perhaps by his party. A Member of his Party was on the Committee. He may have leaked it out.

SHRI BHUPESH GUPTA: No. How do you say it?

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is perfectly all right, because it had appeared in news papers, and the Committee did not take enough care to see that they were making such a preposterous recommendation and that it should not leak out beforehand at least, at least before their report was presented to the House.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश): माननीया, श्री भूपेश गुप्ता ने जो सवाल उठाया है उसके संबंध में मै कुछ कहना चाहता हूं। मै चाहता हूं कि इस संबंध मे एक कमेटी बनाई जाय। जो लोग कमेटी मे बैठते है उनके लिए एक मोरल्टी होती है। वे लोग कमेटी मे तो कुछ कहते हैं, सदन मे कुछ कहते है और पब्लिक में कुछ कहते हैं। इस तरह की चीज राजनीति मे सदाचार के विरुद्ध है। मै हमेशा के लिए यह चाहता हू कि एक नियम बना दिया जाय कि जो आदमी इस तरह की बात करता है उसे कमेटी का मेम्बर न बनाया जाय ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: No Mr. Rajnairain. Now the University Grants Commission (Amendment) Bill.

SHRI A. P. CHATTERJI (West Bengal): The preposterous question regarding the Salary, Allowances and Other Amenities to Members of Parliament and this Report should be placed for discussion in the House.

((*Interruptions by Shri Rajnarain*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

(*Continuted interruptions by Shri Rajnarain*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. You must sit down. Order, order.

THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL, 1968—*contd.*

Clause 3—Amendment of section 6

THE DEPUTY CHAIRMAN: Clause 3 and the amendments thereto.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : माननीया, जब से मैं यहां पर आया हूं तब से मैं बिल तथा अपने अमेन्डमेंट्स की कापी हिन्दी में मांग रहा हूं लेकिन मुझे अभी तक वह नहीं मिली। इस सदन में कई बार आप इस संबंध में व्यवस्था दे चुकी हैं और भार्गव साहब भी दे चुके हैं कि हिन्दी की कापी बिल और अमेन्डमेंट्स की सदस्यों को दी जानी चाहिये। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक ये कापियां मुझे नहीं मिलीं।

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश): आपके घर भेज दी गई होंगी।

श्री राजनारायण : अर्जुन अरोड़ा जी, मौलिक प्रश्नों पर मजाक नहीं होना चाहिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Bill is circulated in Hindi also. The amendments are given in English and they remain in English. Therefore please let us carry on with clause 3.

श्री राजनारायण : हमने तो हिंदी में दिया है।

उपसभापति : आपका अमेन्डमेंट हिन्दी में कहां है ?

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): The constitutional point is that when an amendment is passed, it does not go into the Statute Book in Hindi. It gets translated into English and, naturally, the convention of the House has been that all amendments are only circulated in English and not in Hindi.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It has been translated into English; he gave it in Hindi. Are you moving your amendment No. 13, Mr. Yadav?

श्री राजनारायण : हमारा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है और वह यह है कि जो प्रैक्टिस यहां पर चल रही थी, वह तब थी जब कि लैंग्वेज बिल नहीं बना था। जब एक एक्ट बन चुका है, इस सदन ने उसको पास कर लिया है, तो उसकी मर्यादा का पालन होना चाहिये। जब कोई एक्ट पास हो चुका है तो फिर इस तरह से सदन के मेम्बर यहां पर मजाक क्या करने के लिए बैठे हैं ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: When it goes into the Statute Book it is translated into English; it goes in the English form.

श्री राजनारायण : यह तो पहले की प्रैक्टिस थी। आप हमें बतलाइये जब लैंग्वेज एक्ट के पास होने के बाद हिन्दी के साथ अंग्रेजी रहेगी, तो हमें सब बिलों और हमारे अमेन्डमेंट्स की कापी हिन्दी में मिलनी चाहिये। पहले हिन्दी आयेगी और बाद में अंग्रेजी आयेगी। लैंग्वेज एक्ट बनने के बाद पुरानी परम्परा नहीं रह सकती है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I understand the difficulty. I will look into it and see what can be done, if anything can be done.

श्री राजनारायण : हमारा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि हमने जो अमेन्डमेंट दिया है, उसको कैसे पढ़े ?

उपसभापति : इस क्लाज में आपका कोई अमेन्डमेंट नहीं है।

श्री राजनारायण : हमारा अमेन्डमेंट मिल जाय। आप खुद महसूस कर रही हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है।

उपसभापति : इस क्लाज में आपका अमेन्डमेंट नहीं है।

श्री राजनारायण : मगर मुझे मालूम होना चाहिये कि आप जो कुछ कह रही हैं वह सही है या नहीं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving your amendment, Mr. Yadav?

SHRI J. P. YADAV (Bihar): Madam, I move:

13. "That at page 3,—

(i) in line 2, for the words 'three years' the words 'six years' be substituted; and

(ii) in line 8, for the words 'shall be eligible' the words 'shall not be eligible' be substituted."

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What about your amendments, Mr. Vaishampayen?

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN (Maharashtra): I am not moving my amendments?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Does the hon. Minister accept the amendment.

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN): No, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You please sit down.

श्री राजनारायण : हम नियम की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और संसदीय प्रथा की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने अमेन्डमेंट पढ़ा जाय। अगर माननीय सदस्य अपने अमेन्डमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो वह सदन की प्रापरटी हो गया। कोई भी सदस्य उस के पक्ष या विपक्ष में बोल सकता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I asked Mr. Yadav but he was not quick enough to tell me if he wanted to speak on his amendment. If he does not want to speak I can ask anyone else. I know the procedure and I do not want hon. Members to draw my attention to procedure over and over again.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीया मेरा संशोधन यह है :

13. "That at page 3,—

(i) in line 2, for the words 'three years' the words 'six years' be substituted; and

(ii) in line 8, for the words 'shall be eligible' the words 'shall not be eligible' be substituted."

हमारा इस में कहना यह है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस की 5 वर्ष की अवधि घटा कर 3 वर्ष की की है और उनका तर्क यह था कि अधिक से अधिक लोगों को वह इस में अपार्चुनिटी, मौका देंगे कि वे उस में काम कर सकें। एक तरफ तो वह यह कहते हैं कि शिक्षा वह चीज है जहां पर अनुभवी और विशेषज्ञ लोगों की आवश्यकता है। तीन वर्ष अगर कोई काम करता है और उस ने अच्छा काम किया है, तो वह कहते हैं कि उसको फिर मौका देंगे और दूसरी बार यह कहते हैं कि अगर उन को 6 वर्ष मौका दे देंगे तो एक ही आदमी ज्यादा समय तक काम करता रहेगा और दूसरे को मौका नही मिलेगा। तो एक ही जगह एक बात दूसरी से विपरीतार्थ हो जाती है, एक दूसरे को कन्ट्राडीक्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि 3 वर्ष की जगह वह 6 वर्ष काम करे तो एक ही बार उसे पूरे का पूरा मौका दीजिये। ऐसा देखा गया है कि जब विशिष्ट विषय होते हैं तो उस में एक आधवर्ष अध्ययन करने की जरूरत होती है, इतना समय देखने सुनने में लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यह संशोधन पिछली बार पार्लियामेंट में आया था और पार्लियामेंट एडजर्न हो गयी तो बिल भी समाप्त हो गया। कभी कभी लोग बैठ भी नही पाते और समय बीत जाता है और उन को अवसर नहीं मिलता कि पूरी पूरी उसकी सेवा कर सकें। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि आप छोटे छोटे अमेंडमेंट भी स्वीकार नही करते हैं, इस लिये ही मने कल प्रवर समिति की बात कही थी। अगर उस को आप स्वीकार किये होते तो आपस में बैठ कर, एक दूसरे के तर्क को सुनने के बाद एक दूसरे की बात को समझने के बाद हमे अवसर मिलता लेकिन आपने ऐसा न करके एक साधारण अमेंडमेंट जो था कि कोआपरेटिव सेक्टर, जो आज बहुत प्रामिनेंट हो गया है उस को लिया जाय, इंजीनियरिंग को उस में जोड़ा जाय, उसे भी आप ने नहीं लिया। . . .

उपसभापति : भाषण करने का वक्त नहीं है। खाली अमेंडमेंट वेरी शार्ट और ब्रीफ में रख दीजिये।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : एक शब्द की मैं व्याख्या कर देना चाहता हूं इसलिये कि जब तक मैं अपनी बातों को पूरी पूरी ब्यौरे से विद्वान शिक्षा मंत्री को न बता दूं तब तक वह इसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं होंगे इसलिये कि वह आवश्यक चीज भी उन्होंने स्वीकार नहीं की। मैं समझता हूं कि वह इस लिये स्वीकार नहीं की क्योंकि सदन में सरकार का बहुमत है और बहुमत के बलपर अच्छे विचार भी वोट में, मतदान में गिर जाते हैं। आप ने कल भी देखा कि उस प्रवर समिति के लिये यहां पर कितने ही भाषण हुए, कितने जोरदार भाषण हुए तर्कशील भाषण हुए। वह सारे के सारे प्रवर समिति के पक्ष में थे और वह संशोधन विधेयक प्रवर समिति में इस लिये नहीं जा सका कि आप का यहां बहुमत है। अगर प्रवर समिति में यह जाता तो उनके तर्क आप सुनते और उन पर विवेचन करते और तर्क करते और अच्छे संशोधनों के साथ उस बिल को यहां ला सकते थे। इसलिये मेरा कहना है कि आज भी सिर्फ इसलिये कि आप बहुमत में हैं इस विचार को न ठुकरा दें, बल्कि इस को स्वीकार करें कि 6 वर्ष की अवधि को रखा जाय और उस के बाद आप उन को दुबारा चुनने का अधिकार न दें।

PROF. SAIYID NURUL HASAN (Nominated). I would like to support this amendment which I consider to be of very great importance. This distinguished Education Minister had made a statement yesterday that the term has been reduced to three years so as to provide for greater rotation. Now that is understandable but then he went on to say supposing someone is doing very good work he may be given another term I am assuring that before a person is appointed as a member of the University Grants Commission he must have established his position and made his mark already and the Government would not like to appoint members on probation and it would be influencing unduly the independence of judgment of the members of the Commission if they are to be told that if they behave like good boys they will get another term; if on the other hand they are naughty then they must go out.

श्री राजनारायण : माननीय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में मुझे चूंकि मेरा संशोधन मिल नहीं रहा है मैं समझता था कि इसी भावना से मेरा भी संशोधन कहीं न कहीं अवश्य होगा। यह जो कमीशन है उस का चेयरमैन 5 साल के लिये रहेगा और उस के सदस्य 3 साल के लिये रहेंगे। ऐसा क्यों ? हम को इस तर्क के औचित्य के लिये कोई रीजन नहीं बताया गया है कि ऐसा क्यों। चेयरमैन 5 साल और मेम्बर 3 साल। अच्छा फिर उसी में यह कहा गया है कि तीन साल तक रहने के बाद भी वही लोग दुबारा फिर कमेटी में रखे जा सकते हैं। तो क्या यह एक प्रकार की रिश्वत नहीं है ? यानी तीन साल तक उन मेम्बरों को देखा जायगा, उन को लटकाये रखा जायेगा और सरकार की विशेष कृपा उन पर किस अवसर पर, कैसे हो सकती है इस का इशारा होगा, इस के लिये भृकुटि विलासतायें होंगी। तो इस को देख कर वह मेम्बर अपने स्वतंत्र विचार की अभिव्यक्ति नहीं कर पायेगा। इसलिये मेरा निश्चित मत है कि अगर यह सरकार इस बात को ठीक समझती है कि कोई भी सदस्य तीन ही साल तक सेवा करे तो वह निश्चय करे कि एक बार तीन साल तक काम करने के बाद फिर उनकी पुन नियुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा करने पर तो उन को तीन साल तक रखने की बात में, उस के औचित्य में कुछ दम है, मगर यह कहना कि एक बार हम ने तीन साल कर दिया और फिर अगर हम चाहेंगे तो और तीन साल तक बढ़ा देंगे इस में कोई दम नहीं लगता।

दूसरे, इस में हम को एक असंगति भी लगती है। असंगति यह है कि तीन साल तक रख कर उन मेम्बरों की स्थिति क्या होगी।

[श्री राजनारायण]

आयोग का चेयरमैन 5 साल तक रहेगा, तो उन मेम्बरों को एक प्रकार से चेयरमैन की इच्छा की पूर्ति का साधक बनाया जा रहा है कि चेयरमन की इच्छा के विरुद्ध भी वह सदस्य न जाएं। मेम्बर बराबर यह सोचेंगे कि अगर चेयरमन की इच्छा के विरुद्ध हम जाये तो तीन साल के बाद हमारा मामला ढप हो जायेगा, मगर यदि हम चेयरमैन की हां मे हा मिलाते जायेगे तो चेयरमैन हम को रेकमेड कर सकता है, लिखित रूप मे नही टेलीफोन से या जा कर के कि इन को दूसरे टर्म के लिये भी रख लिया जाय। इसलिये जो तीन साल और पांच साल की असगति की गयी है सदस्यों में और चेयरमैन मे, मैं समझता हूं कि ऐसा कर के इसके सारे गुण का अपहरण कर लिया गया है। इसलिये मैं, महोदया, इतना ही निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर शुद्ध हठवादिता का परिचय न दे, जिद्दी बच्चा न बने और अगर सरकार जिद्दी बच्चा बनेगी तो जिस मकसद को हासिल करने के लिये यह विधेयक यहां लाया जा रहा है उस की पूर्ति नही होगी और यह एक मजाक हो जायेगा।

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal): Madam Deputy Chairman, I think I must echo the sentiments expressed by Prof. Nurul Hasan. As a matter of fact I do not see any justification or wisdom in making such a provision as this that a member snould be for three years if he does the work well, then his term can be extended for another three years. through such a method various kinds of nepotism and patronage are bound to arise. As Prof. Nurul Hasan pointed out it will only lead to attempts to get a good conduct certificate. The member of the University Grants Commission will try to behave 'properly' so that he will get a chance for another term.

Therefore, Madam Deputy Chairman, I think that if the hon. Education Minister could have seen it fit to restore the previous state of things and make the period a little longer, there will be no question of increasing the tenure or increasing the term of service. Instead of three years it can be six years. Let it be six years; but there cannot be any question of increasing the term or repeating the term. Well, if the term is increased or extended and there is no provision for repeating the term, I think, that will bring about a greater independence for the members of the Commission.

SHRI M. RUTHNASWAMY (Madras): Madam, I would like to make a few remarks on this subject because I think that a three-year period is not long enough for a member to do justice to his work, to his capabilities and to the work of the University Grants Commission. Usually what happens is that during this short period of three years, the first year is taken in the member acquainting himself with the details of the administration and the third year is spent in looking forward to the future so that the real work is done only in one year, the second year. So I think in the interests of the University Grants Commission, in the interests of its work, a period of six years should be fixed. I would be in favour of even giving him another terms of six years if he has proved himself satisfactory. But since the amendment cannot be split up into two parts, I would like to support the amendment as a whole in the interests of the work of the University Grants Commission and in the interests of the members' contribution to that work, especially as I am in favour of the portfolio system, namely, members specialising in one branch of the University Grants Commission's work—it would be well if the member was given a longer period in which he could render useful service to the Commission.

DR. TRIGUNA SEN: Madam Deputy Chairman, I explained this yesterday already. I thought of not speaking on this subject. The term of office of the Chairman has been kept at five years and that of the members to three years so there will be a continuity of the Chairman for both sets of members and, as I explained yesterday, the term of office of the members has been reduced to three years because there will be an opportunity for rotation and it is also thought . . .

SHRI A. P. CHATTERJEE: Why rotation?

DR. TRIGUNA SEN: We can have new members also and it has also been found that there are people, eminent people . . .

SHRI A. P. CHATTERJEE: Then why not the Chairman also?

DR. TRIGUNA SEN: How can there be continuity then? As far as members are concerned, there are many eminent persons who are prepared, who may be prepared to work. They are part-time members and they can work for three years. But for six years nobody wants to commit himself. And it is also difficult to get a man for that period.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, are you pressing the Amendment, Mr. Yadav?

SHRI J. P. YADAV: Yes, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

> 13. "That at page 3,—
>
> (i) in line 2, for the words 'three years' the words 'six years' be substituted; and
>
> (ii) in line 8, for the words 'shall be eligible' the words 'shall not be eligible be substituted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

> "That clause 3 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4—Amendment of Section 12

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are five amendments—amendments 15, 16, 17, 18 and 19. Amendment 15 is in the name of Mr. Rajnarain.

SHRI RAJNARAIN: I move:—

> 15. "That at page 3, for lines 28 to 32, the following be substituted, namely:—
>
> 'Provided further that the Commission shall not give any grant to any University which is established after the commencement of the University Grants Commission (Amendment) Act, 1968 without the previous approval of the Commission.' "

PROF. SAIYID NURUL HASAN: I move:

> 16. "That at page 3,—
>
> (i) in line 28, after the words 'Provided further that' the words 'the Central Government or' be inserted; and
>
> (ii) at the end of line 32, after the words 'the Central Government' the words 'till such time as the Commission and the Central Government are satisfied that adequate facilities exist in such University for the maintenance of proper standards' be inserted."

THE DEPUTY CHAIRMAN: Amendment 17 is in the name of Mr. Vaishampayen. Are you moving it?

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: In view of the assurance given by the Minister that special attention will be given to higher education in the backward areas I am not moving amendment No. 17.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Vaishampayen, you are not moving this amendment. The amendment 18 is also in your name.

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: Madam, I want a clarification.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, we cannot come to clarifications now.

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: Madam, let me make a submission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please tell me whether you are moving the amendment or not moving.

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: Madam, depending upon the clarification . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. If you are moving it, you move.

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: I move—

> 18. "That at page 3, after line 42, the following be inserted, namely:—
>
> '(iv) in clause (d), after the words 'University Education' the words 'administration and management' shall be inserted."

THE DEPUTY CHAIRMAN: Amendment 19 is in the name of Mr. Rajnarain.

SHRI RAJNARAIN: I move—

19. "That at page 3, after line 42, the following be inserted, namely:—

'(iv) after clause (i) the following clause shall be inserted, namely:—

"(k) the Commission shall have the right to examine and to see that the grant given by it to a University or an Institution is utilised for the purpose the grant has been made".' "

The questions were proposed.

श्री राजनारायण : माननीया, अब मैं इस अवसर पर आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे शक है कि हमारा हिंदी का जो संशोधन था उसका यह सही अंग्रेजी अनुवाद है या नहीं। क्या मैं आपसे यह निवेदन करने का अधिकार नहीं रखता हूं कि आप कम से कम हमारी हिन्दी वाली कापी मंगा दें...

उपसभापति : आपके पास तो कापी होगी।

श्री राजनारायण : हमारे पास नहीं है। हम को यह शक है कि...

उपसभापति : क्या शक है। आपको ऐसा लगता है कि अमेंडमेंट की अंग्रेजी ठीक नहीं है तो आप बताइयें कि कहां चूक हो गई है।

श्री राजनारायण : बिना संशोधन पढ़े हुये आप मुझे इसके लिये मजबूर कर रही हैं, क्या यह उचित है। जो मैंने अपना संशोधन हिन्दी में दिया है मैं केवल उसकी कापी आपसे मांग रहा हूं। यह हमारा संसदीय अधिकार है।

(*Interruptions*)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इनको संशोधन की कापी मिलनी चाहिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, please speak on your amendment. Please don't take the time of the House on such trifling things. I have told you that we are looking into it and we will see what can be done or what cannot be done.

श्री राजनारायण : माननीया, हमने अपनी पार्टी के संविधान में रखा है कि महिलाओं को विशेष अवसर दिया जाय। उसी को ध्यान में रख कर हम ऐसा कर रहे हैं। यह न समझा जाय कि कोई और चेयरमैन साहब आयेंगे और वह भी ऐसी व्यवस्था देंगे तो हम उसको मान लेंगे। इसलिये बाद में कोई यह न कहे कि मैडम के समय मान गये थे और इनके समय क्यों नहीं मान रहे हो। मेरा अमेंडमेंट यह है

"Provided further that the Commission shall not give any grant to any University which is established after the commencement of the University Grants Commission (Amendment) Act, 1968 without the previous approval of the Commission."

यह करीब करीब वही भाषा है जो कि इस क्लाज की भाषा है। इसमें केवल ये शब्द नहीं हैं. "ऐड आफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।" इसीलिये मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि इसको तो हम दूसरे ढंग से लिख सकते थे कि केवल इतने शब्द निकाल दिये जायं। अब चूंकि हमारा संशोधन यहां पर है नहीं और मुझे बोलना पड़ रहा है साम्राज्यवादी भाषा अंग्रेजी में जो इतने दिनों तक हम पर थोपी गई थी और उसका अनुवाद कर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन बन गया, युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन एक आटोनामस बाडी है और सरकार भी कहती है कि हम उसकी स्वतंत्रता को कायम रखना चाहते हैं तो युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के एप्रूवल से जो विश्वविद्यालय खुल जाय उनको अनुदान देने का हक उसको दे दिया जाय। उसमें "सेंट्रल गवर्नमेंट" का शब्द जोड़ देना अनावश्यक है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस संशोधन का केवल इतना ही मतलब है।

PROF. SAIYID NURUL HASAN: Madam Deputy Chairman, I really do not know whether it is worthwhile saying anything because the attitude of the learned Minister of Education is that he just does not want to consider anything, because twice I made an attempt yesterday, Madam, but still the point was just not answered. I do not want him necessarily to accept my point but I want him to consider it and then if he wants to reject it, he can reject it. The point, Madam, is that the UGC is being told that it should not give a grant to a University which has been established without the previous approval of the Central Government and of the University Grants Commission. But there is nothing to prevent other sections of the Central Government from providing grants to Universities which are established without the approval of the University Grants Commission. I think that this would emasculate the University Grants Commission and I do not think it is going to create a situation in which no new University will be established without the previous approval of the University Grants Commission. Therefore, Madam, I want again, through you, to appeal to the distinguished Minister to consider this that if he adds the words "the Central Government or" along with the words "University Grants Commission" and then debars both the Central Government and the University Grants Commission from giving grants to Universities which have been established without the previous concurrence of the UGC and the Central Government, then it would strengthen the hands of the UGC. It would also make it clear to any organisation or any State Government that no funds from the Central sources would be forthcoming for them.

So far as the second amendment is concerned, I personally think, Madam, that it is worth considering, that is to say, in case, may be after ten years or may be after fifteen years, a University which was established without the previous approval of the UGC starts doing excellent work or raises the standard, then there should be an opportunity to the UGC, after verifying their standards, to give grants. I am especially concerned about some of our finest colleges in the country. Maybe an excellent college, without its own desire, is affiliated to a newly established university. Now, what happens to that college? I think that there should be some provision, whereby the UGC may review the situation. However, if my second point is not acceptable to the Minister, I will not press it, but I would request the Minister kindly to consider my first point, viz., the UGC should not be barred, whereas the Ministries of the Government are permitted to sanction grants.

श्री राजनारायण : माननीया, मैं एक सफाई चाहता हूं नुरुल हसन साहब से। हम चाहते हैं कि उनके सशोधन के हक में हम बोलें, इसलिए जरा मै स्पष्टीकरण चाहता हू। जहा तक हमने नूरुल हसन साहब को समझा है, उनकी तकरीर से इस नतीजे पर हम पहुच रहे हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इजाजत से यूनिवर्सिटी खुलती थी...

THE DEPUTY CHAIRMAN: You speak on amendment No. 19. That is also in your name.

श्री राजनारायण : उसको हमने पढ़ा नहीं।

उपसभापति : पढ़ा ही नही ?

श्री राजनारायण : मैं आपसे कह रहा हूं कि मै आज सीधे चला आया हू।

तो मेरा यह निवेदन है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इजाजत से यूनीवर्सिटिया खुल ी है। तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इजाजत से खुल जायेगीं, मगर अब यनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन बीच में आ गया। यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन अपने फंड्स को देखते हुए विश्वविद्यालय को कुछ ना कुछ सहायता देगी, मदद देगी। नूरुल हसन साहब यह कहना चाहते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट मनमाने तरीके से यूनीवर्सिटी ोलने की इजाज़त देती चली जाय और उसकी कोई जानकारी यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को न हो ? यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को भी जानकारी रहे और सेन्ट्रल गवर्नमेट को भी जानकारी रहे तो क्या दिक्कत है ? सेन्ट्रल गवर्नमेंट को हम यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से ज्यादा मान लें, यह बात मेरे नाकिस दिमाग में नहीं

[श्री राजनारायण]

आती। सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मैं वह निकम्मी से निकम्मी संस्था समझता हूं जो एजूकेशन पर बैठ गई है, यह एजूकेशन को एक्सपेंड करना ही नहीं चाहती है। कम से कम कुछ एजूकेशनिस्ट्स तो यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में कहीं न कहीं से टपक कर आ जाएंगे। इसलिए यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अधिकार को पूरा ले लेना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह पूरा का पूरा क्लाज निकाल दिया जाय। काशी विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी ने बना दिया और फिर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने उसको इजाजत दे दी। हर आदमी को यह हक है कि वह अपने साधनों से, अपनी प्रतिभा से, अपने उद्योग से कोई विश्वविद्यालय खड़ा कर दे, शिक्षा सस्था खड़ी कर दे, खड़ी करने के बाद यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन और सरकार से मान्यता कराए या पैसा मांग ले उसमें क्या बिगड़ जायगा। ये यूनीवर्सिटी से संबन्धित है, इस बारे में मैं इनसे सफाई चाहता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have spoken, Mr. Hasan. No, no.

SHRI RAJNARAIN: It is parliamentary process.

यह संसदीय प्रथा है। एक सम्मानीय सदस्य अपने अमेंडमेंट के हक में बोलें, अगर हम उसे समझ नही पा रहे है तो वे उसकी सफाई कर सकते है। मिनिस्टर साहब क्या जवाब दगे। वे तो जो सरकार की पालिसी होगी उसी की तह मे बोल जाएंगे। त्रिगुण सेन साहब की बड़ी मुसीबत है। वह भले आदमी हैं, कभी अपने व्यू के विरुद्ध भी बोलते है।

प्रोफेसर सैयद नुरुल हसन : मोहतरिमा, राजनारायण जी ने जो फरमाया उस सिलसिले में मेरी यह गुजारिश है कि यूनीवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन और सेन्ट्रल गवर्नमेंट दोनों की इजाजत यूनीवर्सिटियों को खोलने के लिए जरूरी है। अगर यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन उस यूनीवर्सिटी को कोई ग्रान्ट देने की तजवीज करता है तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि आपने यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के हाथ तो बांध दिए, लेकिन मरकजी हुकूमत के हाथ आप नहीं बांध रहे। आप यह सूरत पैदा कर रहे हैं कि यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन कोई इदारा नहीं खोले लेकिन मरकजी हुकूमत की इजाजत से उसको ग्रान्ट देने लगे, यू० जी० सी० न देने लगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do.

श्री राजनारायण : इसमें "एन्ड" हो सकता है। अगर नुरुल हसन साहब का 'आर' मान लिया जाय तो गड़बड़ हो सकती है।

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: Madam, I actually wanted a clarification before I withdrew my amendment, but since I am asked to say something I would like to make a few observations. My amendment arises out of the recommendations of the Kothari Commission in which they have stated that dynamic techniques of administration and management should be evolved. Now, the stage has come and the UGC must give guidance through the different universities, so that this is included. My amendment is a consequence of this particular recommendation of the Kothari Commission. In clause (d) of section 12, if University Education includes "administration and management", my amendment will become a little unnecessary. If the hon. Minister clarifies that 'University Education' in clause (d) of section 12 means "administration and management", I will not press my amendment.

श्री राजनारायण :

"The Commission shall have the right to examine and to see that the grant given by it to a University or an Institution is utilised for the purpose the grant has been made."

माननीया, मैं इस संशोधन को रखना बहुत ही जरूरी समझता हूं क्योंकि हमने यह देखा है कि यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से जो विश्वविद्यालयों को अनुदान मिला है बहुत जगह

उसका सदुपयोग नही हुआ है, बहुत जगह उसका दुरुपयोग हुआ है। मनमाने ढंग से दिल्ली में दस-पांच आदमी बैठ जाये और जनता के धन को इस ढग से देते चले जायं, उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, इसकी जानकारी न करे, यह बात मेरी समझ मे नही आती। इसलिए बहुत सोच-समझ कर हमने यह सशोधन रखा है और मै समझता हू कि नुरुल हसन साहब हमारे इस सशोधन के हक मे बोलेगे क्योंकि उनको बहुत जानकारी होगी विश्वविद्यालय की गतिविधि की, कार्य सचालन की।

इसी की तह मे कुछ रोशनी डालने के लिए कुछ चीजो को मै प्रकाश मे लाऊगा। एक काशी विश्वविद्यालय है। काशी विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के लिए युनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन अनुदान देता है। कोर्ट की पहली मीटिंग मे मै गया, हमारे मित्र नुरुल हसन साहब भी वहा विद्यमान थे। उन बेचारे की मुसीबत हो गई क्योकि इन्होने जो बात कही वह तो सही थी लेकिन वहा चल गया प्रश्न भारतीय कल्चर का। तो भारतीय कल्चर क्या है उस पर इन्होने अपना नुक्तेनजर रखा, मगर कुछ लोगो का नुक्तेनजर मुख्तलिफ था, वे भारतीय कल्चर दूसरी समझते थे और मै बोलने ही वाला था इन के हक मे लेकिन मामला बीच मे गडबड़ हो गया। अब सवाल मेरा यह है कि वहा यह जवाब दिया गया कि अब केन्द्र इस व्याकरण विभाग को चलाना नही चाहता।

उपसभापति : राजनारायण जी, अब खत्म करिए।

श्री राजनारायण : यह अमेडमेट है, इसमें जल्दी मत कीजिए। मै कह रहा था कि व्याकरण विभाग को चलाना नही चाहते। जब हमने माननीय शिक्षा मंत्री और दूसरे साधनों से पता लगाया तो यह पता चला कि नहीं, वहां के अधिकारियों ने ही इस बात को कहा कि व्याकरण विभाग के लिये अनुदान अब बन्द हो जाना चाहिये। उसका मकसद क्या था। यह था कि इस समय व्याकरण विभाग में जो लोग लगे हुये है उनको जब दो चार महीने के लिये अनुदान बन्द हो जाय तो निकाल दें और फिर उनकी जगह अपने मनचाहे लोगों को भर दे और जब मनचाहे लोगों को भर लें तो फिर डा० सेन या कोठारी साहब की खिदमत में हाजिर होवें कि अब हमको ग्राट दे दी जाय और हम फिर उसको चलाने लगें। इस पर दो चार लाख रुपया खर्च हो चुका है और कुछ काम हुआ है। तो मै जानना चाहता हूं कि क्या बिना कोई जानकारी किये हुये, वाइसचांस्लर के कहे बिना, वह ग्राट क्यो बन्द कर दी गई।

माननीया, मै आपकी खिदमत मे यह मोटा पोथा ले कर आ रहा हूं।

उपसभापति : अभी तो आपका अमेंडमेंट है।

श्री राजनारायण : मुझे बताना है कि हमने यह अमेडमेट रखा क्यो। माननीया, मेरी स्थिति कितनी हास्यास्पद हो जायगी अगर इस सदन के माननीय सदस्य समझेगे कि बिना तथ्यों को जाने हम बोल रहे हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You must be very brief.

श्री राजनारायण : हां, बहुत ब्रीफ हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: At the time of moving the amendment you must be very brief and very specific on the points.

श्री राजनारायण : माननीया, मै उतना ब्रीफ हूं जितना कि ब्रीफ हो सकता हूं। आप बीच में न बोले तो हमारी बात दो चार मिनट में खत्म हो जायगी।

तो मै यह अर्ज कर रहा था कि यहां पर एक श्यामलाल कालेज है, श्यामलाल कालेज को 8 लाख रुपये के करीब इस सरकार ने बिल्डिंग बनाने के लिये दिया और शर्त यह है कि इतना ही रुपया ट्रस्ट देगा। जो हमारे पास सबूत है उसके अनुसार जिसको बिल्डिंग बनाने के लिये कहा गया वह संस्था फर्जी है, हमको टेलीफोन का नम्बर दिया गया और उस टेलीफोन पर हमने टेलीफोन किया तो वहां से बताया गया कि यह आदमी यहां रहता ही नही है।

श्री महेश्वर नाथ कौल (नाम-निर्देशित) : बिल्डिंग बनी या नहीं।

श्री राजनारायण : एक हैं सेठ सुन्दर प्रसाद एंड संस, इन्होंने टेंडर दिया। हमारे पास जो तमाम वहां के कागज हैं वह हैं, फोटो-स्टेट कापीज हैं, इनको देखने से मालूम होता है कि उनका टेंडर लोएस्ट नहीं है, ऊंचा है, फिर भी उनको दिया गया। जो दस्तखत मिलाया तो उससे लगता है कि जो श्रीमान श्यामलाल हैं वह किसी दूसरे रूप में सुन्दर प्रसाद बन जाते हैं और वह एक फिक्टीशियस नाम को ले कर के उसके जरिये से सारा हिसाब-किताब बैठा दिया करते हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, you know the procedure.

श्री राजनारायण : तो जब इस तरह की घटनायें घट रही हैं तब हमारा अमेंडमेंट इसकी रोशनी में कितना जरूरी हो जायगा और हम अपील करेंगे कि इसको मान लिया जाय। यह अधिकार हम अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं और न यह अधिकार सरकार के हाथ में दे रहे हैं, यह एक साधु संशोधन है कि कमिशन को यह अधिकार रहे कि वह जो ग्रांट दे उस ग्रांट की उपयोगिता ठीक से हुई या नहीं हुई, उसका सदुपयोग हुआ या नहीं, इसको देखे। यह ज़रूरी है कि इसका हक उनको रहे। यह हमारा संशोधन है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do. Dr. Sen.

DR. TRIGUNA SEN: Madam, regarding amendment No. 15 moved by my friend, Mr. Rajnarain, if I have understood him correctly, the object of his amendment is to delete "Central Government" from the proviso in clause 4. This means that the permission of the University Grants Commission only will be necessary if a new university is established and is desirous of getting grants from the Commission. The Bill provides that in addition to the permission of the University Grants Commission the permission of the Central Government also will be necessary for establishing a new university. There are two aspects of this problem. I wish Mr. Rajnarain listens to me, then he will withdraw his amendment. There are two aspects of the problem. One is academic and the other is financial. The academic aspect is the concern of the University Grants Commission. Nobody questions that and we do not propose to interfere with it. But the financial aspect is the concern of the Government of India which has to provide the money. I therefore think it is necessary to have the approval of the Government of India along with the University Grants Commission. There is yet another point which I want to draw his attention to. Questions about new universities and their establishment are raised in this Parliament. It is the responsibility of the Minister of Education to deal with this. Moreover, he has to come to Parliament to ask for funds for new universities. So it is necessary before a State starts a university to consult the Central Government also. I am sure the hon. Member has understood it and will withdraw his amendment. I appeal to him.

About amendment No. 16, I am sorry, I have never had a closed mind. I explained yesterday to Prof. Nurul Hasan that the principal idea in this proposal is that grants should not be given to a university which has been established without the approval of the University Grants Commission and the Central Government. It was pointed out yesterday that higher education should be in the Concurrent List. I opposed it that it is not practicable, but I want to establish a healthy convention between the State Governments, the Central Government and the University Grants Commission so that they sit together and discuss all points regarding establishing a new university. Again this will act as a deterrent for a State to start fresh universities, as was pointed out by Mr. Chagla, as a prestige question. I hope my friend will understand this viewpoint and withdraw his amendment.

PROF. SAIYID NURUL HASAN: The first point has still not been taken up by the distinguished Minister. I do not know how to draw his attention to it. My main point still is, and I will repeat it, if the University Grants Commission is to be asked not to give a grant, the Central Government must also accept that discipline and not give that grant.

DR. TRIGUNA SEN: That is understood. The amendment is however unnecessary because we are

amending the University Grants Commission Act which deals with the authority of the U.G.C. only.

SHRI ARJUN ARORA: I hope the Minister will agree that what Mr. Nurul Hasan has suggested is a sound policy. Certain norms are being laid down for the University Grants Commission, and if those norms are properly followed by a body which will have some experts and if they arrive at a decision . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has given his reasons. You please go on to amendment No. 18.

DR. TRIGUNA SEN: Regarding amendment No. 18 of Mr. Vaishampayen, it is known to the hon. Member that to regulate the administration and management a model University Act has been drafted which is being sent to all State Governments, to modernise their rules and regulations of the universities. It is also there in the power of the University Grants Commission to see that the standard of education is maintained. Naturally it relates also to the management and administration. A university cannot function or cannot have a good standard of education unless and until the administration is good enough. It is implied in it and the University Grants Commission has got the power according to this Act.

Lastly, again my friend Mr. Rajnarain's amendment, I am sorry I cannot accept it. Madam, it is obviously the function of the grant giving body to ensure that the funds granted are utilised for the purpose for which they have been granted. He has mentioned certain instances of some colleges. The University Grants Commission has got the right to interfere in this matter. If he will hand over the details, I will ask the Chairman of the University Grants Commission to look into them. The provision is there.

श्री राजनारायण : यह राइट उनको पहले से ही है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no reply. You cannot speak again.

श्री राजनारायण : मैं ज़रा जवाब तो दे दूं।

उपसभापति : आप जवाब नहीं दे सकते क्या जवाब देना है!

श्री राजनारायण : यह किस प्रथा के मुताबिक आपने बताया, हमें कोई रूल आप बता दें कि हमारे अमेंडमेंट का मंत्री जी ने जवाब दिया और हम कुछ न कहें, हमको पूरा हक है यह कहने का कि मैं इसको विदड्रा करूंगा या नहीं करूंगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: When I come to your amendment, you can do it.

श्री राजनारायण : और विदड्रा करने के लिये मैं छोटा सा स्टेटमेंट भी दे सकता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Amendment No. 15 which stands in the name of Mr. Rajnarain, are you pressing it or withdrawing it?

श्री राजनारायण : देखिये, जरा सुनिये, मैं विदड्रा क्यों कर रहा हूं यह बताऊं, यह हमारा हक है, आप हमें क्यों दबा रही हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, this is not the practice. You should not make a speech.

श्री राजनारायण : मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा का पालन करूं तो फिर मेरी इच्छा का पालन मुझको करने दीजिये। . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: If one hon. Member should hold up the House like this, how can we go on?

1 P.M.

श्री राजनारायण : मुझे इसके बारे में यही कहना है कि हमने अपनी बात साफ कर दी। अगर हमारा मकसद पूरा हो जाता है और सरकार को इत्मीनान है कि हमारा मकसद पूरा होता है तो मैं इसको विदड्रा कर लूंगा।

**Amendment No. 15 was, by leave, withdrawn.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

*16. "That at page 3—

(i) in line 28, after the words 'Provided further that' the words 'the Central Government or' be inserted; and

*For text of amendment *see* cols. 2446 Supra.

[The Deputy Chairman]

(ii) at the end of line 32, after the words 'the Central Government' the words 'till such time as the Commission and the Central Government are satisfied that adequate facilities exist in such University for maintenance of proper standards be inserted."

The motion was negatived.

SHRI S. K. VAISHAMPAYEN: I beg leave to withdraw the amendment.

**Amendment No.* 18 *was, by leave, withdrawn.*

श्री राजनारायण : देखिये, मैं फिर कहता हूं। एक मिनट मौका तो दें। देखिये, मुझे इस पर कुछ कहना है। साफ बात है, हमारी भी यह इच्छा है सरकार की भी यह इच्छा है कि जो पैसा जाये उसका सदुपयोग हो। मैं इस बात को समझना चाहता हूं, जैसे एक उदाहरण देता हूं। उसको यह सरकार कैसे देखेगी कि उस युनिवर्सिटी के पास क्या पैसा जुटाने का साधन था या नहीं या हमको इतना ग्रान्ट देना चाहिये था या नहीं। यह भी वह चाहते हैं इसमें इन्क्लूड रहेगा। जैसे मैं काशी विवविद्यालय के लिये कह रहा हूं . . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री राजनारायण : सुन लिया जाय। वहां पर अमरीकी एकेडेमी को 120 रु० महीने पर रीवां हाउस की विशाल बिल्डिंग दी गई है जिसमें कम से कम 400 विद्यार्थी रह सकते हैं और 5,000 से 10,000 रु० महीना किराया उसका मिल सकता है। तो जब युनिवर्सिटी के पास खुद पैसे का साधन है और समर्थ है तो उस पैसे के साधन का इस्तेमाल विश्वविद्यालय क्यों नहीं कर रहा है और अगर नहीं कर रहा है तो ग्रान्ट में से उसका पैसा काटा जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे अमेंडमेंट के जरिये यह बातें भी आएं और उसकी उचित रूप से व्यवस्था की जाये।

DR. TRIGUNA SEN: He is withdrawing.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you need not say anything.

श्री राजनारायण : क्या आप हमें संसदीय प्रथा के अनुसार चलने नहीं देना चाहती हैं ?

**Amendment No.* 19 *was, by leave, withdrawn.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That clause 4 stands part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 *was added to the Bill.*

Clause 5—*Insertion of new section 27 Power to delegate.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is one amendment in the name of Mr. Rajnarain. I am told that it is a negative amendment.

The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

श्री राजनारायण : अजीब तमाशा है। निगेटिव्ह अमेंडमेंट पर क्यों नहीं बोला जायेगा?

उपसभापति : नहीं, नहीं।

श्री राजनारायण : यह कहां की प्रथा है? अनावश्यक ढंग से प्रथा बना ली। मैं आपसे फिर अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि निगेटिव्ह अमेंडमेंट पर भी बोला जाता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That amendment is a negative amendment. Even though I have put the clause before the House, I want to permit you to speak on that clause if you want to speak on that.

श्री राजनारायण : मुझे एक निवेदन करना है कि मैं क्यों चाहता हूं कि इसको हटा दिया जाय इसके लिये इसको ठीक से पढ़ा जाय।

"The Commission may, by regulations made under this Act, delegate to its Chairman, or any other whole-time member or officer, its power of general superintendence and direction over the business transacted by, or in,

*For text of amendment *see* col. 2446 Supra.

the Commission, including the powers with regard to the expenditure incurred in connection with the maintenance of the office and internal administration of the Commission."

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह रखा क्यों गया? इसकी जरूरत क्या है। क्या आपने रेस्पांसिबिलिटी को किसी दूसरे के ऊपर फेंकने के लिये रखा है या किसके लिये रखा है। इसका स्पष्ट उत्तर सरकार की ओर से आए।

DR. TRIGUNA SEN : It is just purely a procedure. If the UGC wants to spend Rs. 200 today, the Chairman or anybody has no power to do it till the Commission meets after a month. This should be delegated, for their day-to-day work. It is absolutely procedural. This is under the Act, not beyond the Act.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 *was added to the Bill.*

Clause 6 *was added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

DR. TRIGUNA SEN : Madam, I Move :

"That the Bill be passed."

I crave your indulgence to say something as explanation, if you allow me.

THE DEPUTY CHAIRMAN : But some other Members also want to speak. You can then reply.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill be passed."

SHRI KRISHAN KANT (Haryana): I am sorry, I cannot persuade myself to agree to the explanation given by the hon. Minister of Education. I still feel that this is a very derogatory step which is being taken by the Government of India and one of the most uneducational acts of the Education Minister of the country. The previous composition of the University Grants Commission was nine members out of which two were officials and seven were educationists. The present composition which the Government has brought in is very derogatory and Mr. Vaishampayen's amendment has tried to remove that flaw a little. (*Interruptions.*) You will appreciate the point. There will be 12 members of the University Grants Commission out of which there will be five from the educational sector or the university sector, and one Chairman, about which I have grave doubts because he will be one of the retired Secretaries of the Government of India henceforward—after the retirement of that person. So, even if the Chairman is an educationist, the total number will come only to six out of the number of 12 and only six will be educationists. I do not know how the Education Minister of India is trying to upset the whole balance. Even in an industrial undertaking where the Government has a majority of shares, the Government likes to have a majority of the directors who can watch and safeguard the interests of the Government. We have set up the University Grants Commission to safeguard and promote the standards of education in the country, in which Commission five or six people at the maximum, 50 per cent, will be educationists. They will not be able to safeguard the interests of education in the country, and that is being done by the Education Minister. So, I have grave doubts on this. This is a very retrograde step for which I record my strong protest. Yesterday the Education Minister was kind enough to dismiss what I said as being youthful fervour and all that. May I tell him that the demand of France, the demand of Germany is that they do not want education to be administered only by the educationists but by the students themselves. But here you are taking away from the educationists and giving to those persons who are not committed to education. Yesterday while replying he said, I have pleaded in this House that education should be productive, there should be productive relationship with education. I still stand by it. But I do not give 50 per cent to those people. This is a very important contribution. It is going to the Statute Book. This is going to change the whole structure of the University Grants Commission. This is very important. Just as we have got in the Press Council, we could have a reservation of two persons of industry and commerce. The Press Council

[Shri Krishan Kant]

Bill, you remember, we created; we discussed a lot of things. Working journalists were members of the Council. Out of 25 members the majority were working journalists. We are unable to safeguard even though our educationists—Professors and Vice-Chancellors—are being driven away like dumb cattle. Give them majority. That point should be covered. There should be given a reservation of two seats and the rest could be educationists from the fields of Agriculture or Medicine. This is very important. I am afraid, when you want to put some Educational Adviser or some Agricultural Adviser, somebody from the Government will go there as the Educational or Agricultural or Medical Adviser. If you want them, take them from Universities, take them from Medical Colleges. What you are providing for is contradictory to what should have been done and I feel this will ruin our education. I think this is a great joke being played by the Government of India on the education of this country.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Chandrasekharan.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala) : Madam Deputy Chairman . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh) : One minute I want to say something. It is not much, Mr. Chandrasekharan. I think the point that has been drawn attention to by my friend, Mr. Krishan Kant, will be considered by the Education Minister. If the hon'ble Education Minister gives the assurance that on the whole the majority will be of educationists and even for Medicine and Agriculture there will be educationists, that will go a long way to satisfy us.

DR. TRIGUNA SEN : We will keep that in view.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Had you given this assurance, there would not have been all these speeches during the Third Reading.

SHRI K. CHANDRASEKHARAN : Madam Deputy Chairman, the provisions of the Bill are obviously intended to improve the functioning of the University Grants Commission. But I am not sure, Madam, how far in actual working and practice things will improve. The most important aspect of University education, particularly in the circumstances and economic conditions that exist in this country at present, is the assurance to the public at large and to the students particularly that there will be contented teaching staff in the colleges in this country. We find, Madam, that in spite of the fact that the University Grants Commission stands for one scale of pay for teachers in the colleges, different scales of pay continue to exist for teachers in private colleges, for teachers in Government colleges and for teachers in colleges directly functioning under the Universities, all doing practically the same type of work, and it is up to the University Grants Commission, who implement the provisions of this Bill and the Act particularly, to see to it that at least in future the discrimination existing against the teachers in the private sector colleges is put an end to and they are placed on par with their counterparts in the Universities and in the Government colleges. They should see to it that the Government and the Universities concerned provide the necessary matching grant for this purpose. This is one aspect.

Very briefly, Madam, the second aspect that I would like to dwell on is this. Particularly at this stage and in discussing the provisions of this amending Bill, I would like to bring to the notice of the hon'ble Minister the necessity for the establishment of a full-fledged Hindi-medium teaching University in the South preferably, if I may say so, in the State of Kerala, if I may be excused. And for this purpose it is up to the Central Government and the University Grants Commission to see to it that cent per cent. funds are provided for such a teaching medium University in Hindi, the national and official language of this country in an area where Hindi is being taught compulsorily from even the primary stages. I, therefore, submit that this aspect should also be taken into serious consideration by the University Grants Commission.

Thank you, Madam.

SHRI KESAVAN (THAZHAVA) (Kerala): Madam, the University Grants Commission is constituted mainly for the purpose of giving grants. But these grants should not be given to those institutions the Managers of which receive bribes for the admission of students and also for the appointment of teachers. Madam, in Kerala, more than 70 per

cent. of the colleges are run in the private sector, mostly by communal organisations. There, for admission to pre-degree classes they take Rs. 500. For B.A. and B.Sc. classes they take a bribe of up to Rs. 2,000. If a student wants admission to B.Sc. (Chemistry) he has to pay Rs. 3,000 and for M.Sc. in Chemistry Rs. 5,000. For the appointment of Lecturers they take Rs. 5,000 to Rs. 10,000. These are the things which now take place.

SHRI LOKANATH MISRA: In spite of your Government being there.

SHRI KESAVAN (THAZHAVA): Government can do nothing in this matter. It is not only in Kerala, everywhere this is going on. I may submit that running of schools and colleges in the private sector is the most profitable industry nowadays. They are making immense profits out of this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI KESAVAN (THAZHAVA): Let me give you one recent example. Not one or two, but 37 lecturers who were employed on probation under one management which conduct twelve colleges, were given notices dispensing with their services alleging that they were inefficient. But 24 of them approached through proper channels . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is the Third Reading. You should have told all this at the consideration stage.

SHRI KESAVAN (THAZHAVA): . . . They approached through proper channels and gave a petition to the effect that they would teach efficiently in future. The words "proper channel" must be underlined. Some others, nine in number, were not taken and now a strike is going on . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

SHRI KESAVAN (THAZHAVA): . . . Now so many things are taking place. What I am submitting is that the University Grants Commission must make rules so that those institutions which receive these amounts for admission as well as for appointments do not get grants.

SHRI M. RUTHNASWAMY: Madam Deputy Chairman, the suggestion of Mr. Krishan Kant in regard to the composition of the University Grants Commission will be tested by the constitution of the first University Grants Commission under this Act and I hope and trust that the Minister in constituting the first Commission under this Act will see to it that even those members who represent Commerce, Industry or Agriculture will be people who have some intimate touch with education, who have some interest in education and are not mere technocrats or specialists in industry, not merely plutocrats who may be said to be representatives of Industry, Commerce and Agriculture . . .

DR. TRIGUNA SEN: Thank you for the suggestion.

SHRI M. RUTHNASWAMY: Since this will be the first composition of the U.G.C., people from Commerce, Industry and Agriculture, who have an intimate interest and association with education should be appointed as members.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajnarain. (*Some hon. Members stood up in their seats.*) I cannot call very many people now. In the next five minutes we must finish this Bill.

SHRI MULKA GOVINDA REDDY (Mysore): I will take two minutes, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then he will take three minutes.

श्री राजनारायण : हम को इस के बाद ज्यादा समय मिलना चाहिये । माननीया, मैं यह समझता था कि जब यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के संबंध में कोई संशोधन विधेयक पेश होगा तो अब तक की जो खामियां रही हैं उन को दूर करने का प्रयत्न होगा, मगर मैं यह देख रहा हूं कि इस विधेयक से कोई खामी बुनियादी तौर से दूर नहीं हो पा रही है और मुझे अफसोस है कि काफी रुपया खर्च हुआ जिस समय कि नेशनल इंटिग्रेशन के नाम पर बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े मंत्री, नेता शिमला में जुटे । जब संशोधन आया तो इस संशोधन में और मंत्री जी के दिमाग में शिक्षा और सरकार इन दोनों में क्या संबंध है, शायद यह स्पष्ट नहीं हो पाया । 1947 से यह मुल्क आजाद है । 21 साल व्यतीत

[श्री राजनारायण]

हो गये और हर आदमी नाम लेगा महात्मा गांधी का, हर आदमी नाम लेगा कांग्रेसी विनोबा भावे का, हर आदमी ऊंचे ऊंचे आदर्श वाक्यों का यहां पर मनन करता है और उद्घाटन करता है। मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो जनतंत्रीय पद्धति और प्रणाली के मानने वाले लोग हैं, जो इंडियन फिलासफी के बहुत ज्ञाता बनते हैं, हमारे नवाब साहब हैं, उन से मैं पूछना चाहता हूं कि . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is third reading. You have spoken at the consideration stage and you have spoken on the amendments also. If you have any salient points, you can mention them now.

श्री राजनारायण : आखिर यह विधेयक क्या है ! यह विधेयक शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाता है या शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से उन्मुक्त करता है। यह फंडामेंटल बात है। यह बहुत ही मौलिक बुनियादी सवाल है। अगर कोई कहे कि हम जनतंत्री है और अगर कोई कहे कि शिक्षा को सरकार के नियंत्रण से अलग रखना चाहिये, और हमारे शिक्षा मंत्री जी शायद इसी सिद्धांत के मानने वाले हैं कि शिक्षा पर जितना ही सरकार का नियंत्रण बढ़ता है उतनी ही शिक्षा प्रणाली दूषित होती है . . .

एक माननीय सदस्य : यह गलत बात है।

श्री राजनारायण : यह डिक्टेटरशिप को मानने वाले हैं। इस लिये पहला जो हमारा बुनियादी मतभेद यहां पर है वह यह कि यह यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन (संशोधन) विधेयक जो मौलिक प्रश्न आज देश और दुनिया के सामने उठा हुआ है उस की पूर्ति नहीं करता। यह सरकारी नियंत्रण को शिक्षा में और बढ़ा रहा है और दूसरा जो हमारा विरोध है वह यह कि रोज हम हल्ला करते हैं कि हिन्दू नाम, मुस्लिम नाम, राजपूत नाम, ब्राह्मण नाम, जाति द्योतक, संप्रदाय द्योतक संस्थाओं को मदद नहीं होनी चाहिये। सभी लोग जवाहरलाल नेहरू से ले कर नवाब साहब तक इस बात को चिल्लाते हैं। यह मुझे मालूम है। मेरे मित्र श्री नूरुल हसन साहब पता नहीं हमारी इस बात का समर्थन करेंगे या नहीं कि हम एक कलम से यहां लिख दें कि उन एज्यूकेशनल संस्थाओं को, यूनिवर्सिटीज को, जिन में सांप्रदायिक, मजहबी या जातियों का नाम होगा उन को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन एक पैसा भी मदद नहीं करेगा या जो विश्वविद्यालय अपने यहां साम्प्रदायिक भावों से पोषित संगठनों को प्रश्रय देंगे उन विश्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन एक पैसा मदद नहीं करेगा। आखिर ये शब्द हैं क्या ! यह चूं चूं का मुरब्बा है या केवल कहने के लिये हैं या किन्हीं लोगों को आकर्षित करने के लिये है। यह हमारी मानवीय दृष्टि है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? आज 21 वर्ष भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए हो गये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का स्वरूप क्या है। इस लिये मैं बहुत ही नम्र शब्दों में . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you have said all this.

श्री राजनारायण : और इस के साथ श्री त्रिगुण सेन जी से निवेदन करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि उन की शिक्षा में अभिरुचि है, वह ठीक तरीके से अभी इस विधेयक को वापस लें और एक अच्छा, बढ़िया विधेयक, जो कि मानवता को प्रतिष्ठित करे, शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है–मनुष्य के सभी गुणों को विकसित करने का उचित अवसर उपलब्ध कराना–उसे लायें क्योंकि शिक्षा का सही उद्देश्य ही है अधिकतम स्तर पर जा कर मानवीय गुणों का विकास करना और विश्व मानवता को प्रतिष्ठित करना। अगर शिक्षा का यह उद्देश्य नहीं है तो आज ग्रान्ट्स कमीशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। जो मौलिक प्रश्न हैं इस क्षेत्र में उन में से किसी को यह विधेयक छूता नहीं है इस लिये मैं आप के जरिये चाहूंगा कि वे इस विधेयक को वापस लें और एक बढ़िया, संयत, साधु दृष्टिकोण रखते हुए, जनमत का ध्यान रखते हुए एक विधेयक यहां पर सरकार की ओर से प्रस्तुत हो यह मेरी इच्छा है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have finished?

श्री राजनारायण : नहीं नहीं । आप खड़ी हुई हैं इसलिये मैं चुप हूं । जब चेयरमैन खड़ा हो तब मैं बोलता रहूं मैं इतना धृष्ट नहीं हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have already taken more than the time allotted for this. I request Members to mention only the salient points in a few sentences during the third reading.

श्री राजनारायण : माननीया, हम लोग पार्लियामेंटरी पद्धति में दस, पांच वर्ष गुजारे हैं । हम लोग जानते हैं कि तीसरी रीडिंग में क्या होता है । कभी कभी थर्ड रीडिंग में फर्स्ट रीडिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं । तो दूसरी बात, जो इस कमीशन का कंपोजीशन है . . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot go on and on like this repeating the same things.

श्री राजनारायण : आप जायं । वह निर्वाह कर लेंगे ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the Minister has also another engagement at 1-30 and I request that this business may be finished by that time.

श्री राजनारायण : तो मिनिस्टर के इंगेजमेंट के मातहत यह सदन नहीं होगा । यह सदन सर्वोपरि है न कि मिनिस्टर का इंगेजमेंट ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair.]

देखिये कितनी गलत बात यहां पर कह दी गयी कि चूंकि मिनिस्टर का एक इंगेजमेंट है इस लिये हम यहा इस बात को न कहें । यही बातें संसद की मर्यादा को भंग करती हैं ।

तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जो कंपोजीशन है, जो गठन है आयोग का, जरा उस गठन को चेयरमैन साहब आप देखें । उस के अनुसार सरकार के हाथ में सारी ताकत है । सरकार चेयरमैन चुनेगी, सरकार ग्यारह मेम्बर चुनेगी, कैटेगरीज दे दी गयी है कि इन इन में से चुनेगी लेकिन वह चुनते समय सब निरर्थक होगा । सरकार जिस को चाहेगी उस को इंडस्ट्रियलिस्ट बना देगी, जिस को चाहेगी एग्रीकल्चरिस्ट बना देगी, जिस को चाहेगी कोआपरेटिव का एक्सपर्ट बना देगी । इस लिये जिस सरकार के हाथ में इतनी बड़ी ताकत रहे वह क्या डेमोक्रेटिक सरकार कही जायगी । हिटलर के हाथ में क्या इस से ज्यादा ताकत थी ? सारी की सारी एजूकेशन पहले उस ने अपने हाथ में ली और एज्यूकेशन को अपने हाथ में लेकर उस ने लोगों के दिमाग को बेढंगा बनाया । इस लिये जो हम ने संशोधन इस में किया था अगर अब भी वह सरकार के दिमाग में हो तो इस विधेयक को वह वापस लें । जैसे कि हम ने केवल यही कहा था कि प्रेसीडेंट इस कमीशन के चेयरमैन को नामिनेट करे । यह हमारा संशोधन था । प्रेसीडेंट प्रायः सरकार की सम्मति लेता है मगर प्रेसीडेंट को, अगर यह अधिकार रहेगा, और कोई अच्छा प्रेसीडेंट हो तो वह अपने अधिकार का इस्तेमाल कर के, सरकार की राय की उपेक्षा कर के किसी दूसरे को भी चेयरमैन बना सकता है । तो जो भारतीय गणतंत्र का राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति को यह ताकत देने के लिये आप की यह सरकार तैयार नहीं है । वह कहती है कि नहीं, श्री त्रिगुण सेन जी ही, श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से जो बात आयेगी उसे ले कर किसी को नामिनेट कर देंगे ।

इसी के साथ साथ मेम्बरों के चयन के बारे में भी हमारी अपनी बात पहले ही आ चुकी थी । जिस ढंग से मेम्बरों को गठन कराया जा रहा है वह अनुचित है । एक तरफ तो त्रिगुण सेन जी ने अपने जवाब में कहा कि इस के दो पहलू हैं—एक आर्थिक और एक शैक्षणिक । शैक्षणिक पहलू तो हम कमीशन के हाथ में रख रहे हैं, लेकिन आर्थिक पहलू हम सरकार के हाथ में रख रहे हैं और इस कमीशन का गठन क्या होगा ? शैक्षणिक, नहीं शुद्ध सरकारी । शुद्ध सरकारी । तो हम ने संशोधन में केवल यह रखा था कि जो इस कमीशन के मेम्बर चुने जायं उन का चुनाव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, कालेजेज के प्रोफेसर्स तथा टीचर्स द्वारा हो, क्योंकि जो उस काम में लगे हुए

[श्री राजनारायण]

हैं वह जानते हैं कि कौन एजूकेशनिस्ट है, किस की शिक्षा के क्षेत्र में कितनी पहुंच है। अगर उन सब को यह अधिकार दे दिया गया होता तो हर्ज क्या होता।

दूसरी बात मुझे यह भी कहना है कि कोई वाइस चांसलर है और अगर वह कमीशन की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है तो उस को कमीशन का मेम्बर बनाने में आपत्ति क्यों हो? हां, मेम्बर बनने के बाद वह वाइस चांसलरशिप से हट जाय। आज जो मौजूदा वाइस चांसलर है अगर वह कमीशन में जा कर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ज्यादा उपयोगी हो सकता है तो वाइस-चांसलर रहते हुए भी मेम्बर हो जाय, लेकिन ज्यों ही मेम्बर हो जाय उस के बाद वह वाइस-चांसलरशिप से इस्तीफा दे दे। तो यह इतना अच्छा संशोधन था, जनतंत्रीय था। इसे मान लेने से सरकार का खूनी पंजा शिक्षा के क्षेत्र में जा कर शिक्षा को दूषित नहीं कर पाता। थोड़ी सी गुंजाइश इस की थी। यद्यपि इस संशोधन के द्वारा हम पूरा सुधार नहीं कर सकते, जब तक कि हम पूरी तरह से इस क्षेत्र में बदलाव न करें शिक्षा की स्थिति सुधर नहीं सकती। आज शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वह हमारे संशोधन से भी नहीं होता मगर उस से कुछ अंकुश अवश्य लगता है। इस लिये मैं चाहता हूं, आप के जरिये अर्ज करता हूं हुजूर, कि सरकार इस विधेयक को वापस ले और इस के बाद एक सीधा, सामयिक, सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए पूरा विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करे।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : शुक्रिया।

SHRI MULKA GOVINDA REDDY : Mr. Vice-Chairman, I had already drawn the attention of the Minister with regard to the scales of pay of teachers in the universities. With your permission I would like to read from the UGC Report for the year 1965-66, page 33. It says :

"The Commission has repeatedly emphasised that the success of all plans of development largely depends on the ability and devotion of teachers. The most important component of an institution of higher learning is obviously the teachers. It is necessary to attract a reasonable proportion of our men and women of high intellectual ability to the teaching profession. There can be little progress in the field of higher education if universities and colleges are not able to recruit and retain sufficiently qualified staff. The provision of reasonable salaries and the essential amenities and incentives for the teaching profession are an important factor in the maintenance of proper standards of education."

It is evident from this that we must do everything possible to improve the scales of pay of teachers in the private colleges, in the Government colleges and in the university colleges. This artificial distinction should not be allowed to continue for long. My hon. friend has rightly put it that something should be done to see that the scales of pay of all teachers in all the colleges are brought on a par. I am afraid the Central Government and the UGC have not bestowed much attention on this, though to some extent they have fixed the scales of pay for teachers in different colleges. That distinction should not be there and they should see that everything possible is done to see that the scales of pay of teachers in all the colleges are brought on a par.

Secondly, I would like to add that the number of students is increasing day by day but in the same proportion the number of teachers is not increasing. So something should be done to retain the ratio with regard to teachers and students on a reasonable scale.

Lastly, Mr. Vice-Chairman, in almost all the universities in most of the States now there is a tendency to have regional languages as the media of instruction. I for one feel that English should continue to be the medium of instruction for a long time to come and when it is replaced, it must be replaced by Hindi. Otherwise there will be babelisation. After some years a Maharashtrian might feel himself to be a stranger in Karnataka. Therefore in order to maintain unity and integration, when we think of changing the medium of instruction in the universities, English should continue to be the medium of instruction of course, but when it is to be replaced, it must be replaced by the national language. Thank you.

SHRI M. M. DHARIA (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, my hon. friend, Shri Krishan Kant, has raised a very vital point with regard to the composition of the UGC. As you rightly said, the hon. Minister should necessarily assure this House that the majority in the UGC will be of educationists. At the same time I would like to request through you the hon. Minister that this Bill will be going to the Lok Sabha. In the meantime, he should give thought to this proposition, because it is not the assurance that permanently remains on record; it is the statutes which remain permanently on record. Therefore he should apply his mind from that point of view and see that it is properly amended Even if it comes to this House, we shall not take more time but we shall all co-operate with the hon. Minister. I would appeal to him therefore to look at this matter from that point of view. Thank you.

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, I am sorry that I have to intervene in this debate at this late stage. I have been very unhappy since clause 2 was passed yesterday about the composition of the Commission. A stage may arise when out of 12 members 7 members may be non-educationists. This is a very unhappy position. A very healthy provision which exists in the present measure has been dropped unceremoniously. I would like to know from the hon. Minister the reasons for the same. The provision I am referring to is the present section 5, sub-section (3) which reads as follows :

> "The Central Government shall nominate a member of the Commission, not being an officer of the Central Government or of any State Government, to be the Chairman thereof."

This clause was deliberately put there to exclude officers heading the UGC. Now this has been dropped which means that in future the Chairman of the Commission can be an official. This is how subtlely the bureaucracy works and the Ministers are caught napping. I still hope that in the Lok Sabha the Minister will not be averse to the appointment of a Select Committee to go into this Bill, so that the lacunae which have not been rectified in this House may be rectified there and when the UGC (Amendment) Bill becomes an Act, it is a perfect Act and education remains in the hands of educationists, not in the hands of pseudo educationsists or non-educationsists and the UGC should not be headed in any case by an official of the Government of India or of any State Government for that matter.

DR. TRIGUNA SEN : Respected Vice-Chairman, Sir, I would like to make a clarification. I am very unhappy that several Members feel that the Bill will bureaucratise the UGC and make it possible for Government to appoint more and more officers on it. Sir, if we compare the old Act with the amended Act, we find that this is not so. Under the old Act the total number of members of the UGC was 9. It had two officers of the Central Government as members. It was also further provided that not less than half the total number of members shall be from among persons who are not officers of the Central Government or any State Government. In other words, the UGC of 9 members had two Government servants necessarily as members and as many as four of its members might have been Government servants. Under the amended Act the UGC will consist of a Chairman and 11 members. I made clear that the Chairman of the UGC shall be an educationist of repute, respected in the academic community. The remaining 11 members will be there and out of them 5 will be from the universities, 2 Central Government servants as in the old Act. The remaining 4 members are to be appointed so as to represent various interests such as industry, agriculture, medicine, etc. They will naturally be interested in the furtherance of education in their respective professions or will be educationists. Of these not more than 2 can be Government servants. Sir, I want to make it clear that while appointing these four members the first and the only consideration before the Government will be academic competence of the persons concerned. If an eminent person in this field, say, a good professor in a Government college is selected for membership of the UGC on the basis of his own academic competence, I see no reason why he should become ineligible for appointment as a member of the UGC only on the ground that he happens to be a Government servant. It will thus be seen that under the old UGC Act providing for 9 members the number of officers was the minimum of two and the

[Dr. Triguna Sen]

maximum of four; in the new U.G.C. of 12 members the number remains the same, the minimum of 2 and the maximum of 4. This is in keeping with the recommendations of the Education Commission which said that not more than one-third of the members of the U.G.C. shall be Government servants. It is obvious that no weightage is given to the official members in the new U.G.C. Four out of twelve is less than four out of nine. The Bill therefore reduces the bureaucratisation rather than increases it.

Some misunderstanding has been caused by the omission of sub-section (3) of section 5 of the old Act which said:

"That the Central Government shall nominate a member of the Commission not being an officer of the Central Government or of any State Government to be the Chairman thereof."

It has been inferred hastily that the omission of this sub-section shows an intention on the part of the Government to appoint a Government servant as the Chairman of the U.G.C. Nothing can be farther from the truth but let me first explain why the clause was necessary in the old Act and why it is not necessary in the amended Act. In the old Act the procedure prescribed was to constitute the U.G.C. first and then to nominate a member of the U.G.C. as Chairman. When the U.G.C. was constituted, it consisted of 9 members of whom 2 had to be servants of the Central Government and 2 others might also be servants of the Central or State Governments. In order to ensure that the Chairman was nominated from among the non-official members only, a specific provision was necessary and so sub-section (3) was added in the old Act but in the amended Act this contingency does not arise. The Chairman is not nominated now from among the members of the U.G.C. He is appointed independently on his own merit and then he becomes a member of the U.G.C. automatically. In this situation it was considered necessary to retain the old provision. Let me categorically place on record the policy of the Government in this matter. The Chairman of the U.G.C. shall be an educationist, respected in the academic community. He shall not be an employee or a Government servant. The Government believes that the autonomy of the U.G.C. is absolutely essential for the improvement of higher education. The Government therefore will do everything in its power to strengthen that autonomy and to ensure its academic independence.

With these words, I request that the Bill, as amended, be passed.

SHRI M. P. BHARGAVA: What assurance the Minister has been pleased to give here, I would like it to be incorporated in the Statute when it goes to the Lok Sabha so that there can be no misunderstanding in the future. To-day Dr. Sen is the Education Minister, tomorrow somebody else may be the Minister and it must come on the Statute Book.

SHRI KRISHAN KANT: I would like to bring to the notice of the Minister that what he has said are very good, pious hopes. We have experience of the Press Commission where the Chairman of the Press Commission was appointed by the Chief Justice of India. Only a retired judge or one who resigned became the Chairman. That is what I fear is going to happen here also. The Education Secretary may retire two months before and he will be made the Chairman of the U.G.C.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI AKBAR ALI KHAN): The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

THE INTER-STATE WATER DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 1968

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER. (DR. K. L. RAO): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Inter-State Water Disputes Act, 1956, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

I will briefly submit the reason for bringing up this amendment. Rivers can be engines of destruction as it has been in the case of Tapti, for example, to-day, or Narmada or Brahmaputra but if controlled and developed properly, they can be the greatest and inexhaustible treasures of the nation.